RAJYA SABHA

Thursday, the 25th August, 2005/3 Bhadrapada, 1927 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Approval to NCLP for Thane and Solapur

*421. SHRI TARIQ ANWAR: †
SHRI DATTA MEGHE:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government had accorded approval to the National Child Labour Projects under the Child Labour (P&R) Act, 1986 for Thane and Solapur in 1995 and for 11 other districts in the years 2003 and 2004;

(b) if so, the details thereof, the facilities and support provided to child labour thereunder and the number of children covered in Maharashtra under the scheme;

(c) whether Government of Maharashtra has proposed some more districts in the State to be covered under the National Child Labour Projects;

(d) if so, the details thereof; and

(e) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

---

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Tariq Anwar.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Under the National Child Labour Project (NCLP) Scheme, in addition to Solapur and Thane, 11 more disdtricts of Maharashtra, namely, Nanded, Yavatmal, Dhule, Beed, Nasik, Pune, Ahmednagar, Sangli, Kolhapur, Jalgaon and Nandurbar have been included under NCLP Scheme in the year 2004. Under the National Child Labour Project Scheme, Special schools/Rehabilitation Centres are set up, which provide following facilities to the children withdrawn from employment:

Formal/Non-formal education;

Vocational Training;

Supplementary nutrition @ Rs. 5/- per child;

Stipend @ Rs. 100/- per month to children withdrawn from employment;

Health care facilities.

So far, 3,700 children are being covered under the Scheme in the two old districts of Thane and Solapur. Based upon the recommendations of the State Government, Nanded, Nasik, Yavatmal and Beed, have been recently sanctioned 25, 44, 2 and 25 special schools for child labour respectively in the year 2005, which will cover 4800 children. However, in the case of rest of the selected districts, namely Dhule, Pune, Ahmadnagar, Sangli, Kolhapur, Jalgaon and Nandurbar, the proposals for special schools for Child Labour from the State Government are still awaited.

(c) to (e) The State Government of Maharashtra has submitted 15 proposals for inclusion of districts under the NCLP Scheme between 1999 to 2004. The NCLPs are selected by the Government on the basis of the endemicity of child labour as per the census data. The Scheme was being implemented in 100 districts till the 9th Plan. It has subsequently been expanded, during the 10th Plan, to cover 250 districts in the country, based on the census figures of 2001. Accordingly, Pune, Ahmednagar, Sangli, Kolhapur, Jalgaon, Nandurbar, Nanded, Nasik, Yavatmal, Dhule and Beed have been selected from the State of Maharashtra for implementation of the NCLP Scheme.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि 2001 की जनगणना के आधार पर देश में 250 जिलों को नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के दायरे में लेने के लिए 10वीं योजना के दौरान इसका विस्तार किया गया है। इसका मतलब है कि अभी भी साढ़े 400 जिले इस नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट से वंचित हैं। सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने दिसम्बर, 1996 में एक writ petition के जवाब में एक जजमेंट में एक direction दिया था। These directions included payment of compensation amounting to Rs. 20,000 by the offending employer. तो जो directive दिया गया है, इस दिशा में सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है?

मेरा B प्रश्न यह है कि the study commissioned by the Ministry of Labour on evaluation of the NCLP has pointed out very low level of enrolment in the case of projects run in Maharashtra. Maharashtra being an otherwise prosperous State, this is surprising. तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर इसका क्या कारण है?

श्री सभापति: ठीक है।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, according to the Census figures the child labour in Maharashtra is on the decline. According to 1991 Census, the child labour was about 10.68 lakhs. According to 2001 Census, it has come down to 7.64 lakhs. We all know, particularly, Mumbai and its suburbs attract inter-State migrant labourers from all over the country and, as a result, Mumbai faces this kind of a problem. Immediately after seeing the Press reports and the TV reports, the Ministry has ordered a thorough survey from the Government of India itself. We are going to undertake a survey in Mumbai and, particularly, in its suburbs, and also in the National Capital Territory of Delhi.

श्री तारिक अनवर: महोदय, चाइल्ड लेबर को समाप्त करने के लिए क्या ऐसी जानकारी भारत सरकार को या लेबर मिनिस्ट्री को है, जिसमें यू॰एस॰ डिपार्टमेंट के साथ INDUS के नाम से एक प्रोजेक्ट चलाने की संभावना है? अगर है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे कितना लाभ होगा और इससे कितने बच्चे प्रभावित होंगे?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, as per the Ninth Plan, the allocation provided for eradication of child labour in the country was Rs. 178 crores and this has been increased to Rs. 602 crores in the Tenth Plan. Across 21 States in the country, now we have taken up 250 districts where the NCLP programme is carried out. Simultaneously, in

collaboration with the United States of America, we have taken up the INDUS Project in 21 districts of the country. About 80,000 children are being benefited out of this Indo-Americal joint venture.

श्री दत्ता मेघे: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जैसा कहा गया कि पुनर्वास किया गया है, तो अभी तक उद्योग क्षेत्र से ऐसे कितने बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उनका पुनर्वास किया गया है? सर, मुम्बई में अभी दो महीने पहले, एक महीना पहले पुलिस ने कम से कम दो सौ, तीन सौ बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे थे, उनको इससे बाहर निकाला था और यह जो पुनर्वास की बात कही है कि वहां पर सात सौ बच्चों के लिए महाराष्ट्र में पुनर्वास की सुविधा है, यह सुविधा बराबर नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय जिन बच्चों को बाजू करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए जो भी योजना बनाई गई है, उसके बारे में कोई इंपलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना के बारे में आप क्या कर रहे हैं? सर, उन बच्चों को वापस बिहार और उत्तर प्रदेश में भेज दिया है।

श्री सभापति: आप कह रहे हैं कि बाजू करते हैं, यह बाजू का क्या मतलब है?

श्री दत्ता मेघे: सर, छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये खतरनाक उद्योग हैं, इसलिए मैंने पूछा है। ...(व्यवधान)... बाजू, हमको हिंदी बराबर नहीं आती है, सर। ...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: बाजू मायने साइड कर दिया है, सर। ...(व्यवधान)...

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, ऐसा है कि जहां से भी कंपलेंट आती है, हम इन्क्वायरी करते हैं, इन्सपेक्शन करते हैं। उसी प्रकार महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र के लेबर डिपार्टमेंट, दोनों ने मिलकर ज्यायंट रेड किए थे, जिनमें करीब-करीब 400 बच्चे एक जगह और 275 बच्चे दूसरी जगह मिले थे। उन बच्चों में काफी बच्चे वेस्ट बंगाल और बिहार के सीतामढ़ी और दरभंगा से थे। बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी में भी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट अमल में है, लागू में है, इसलिए वहां बच्चों की सुविधा के लिए उनके अपने राज्य में, जहां वह प्रोजेक्ट लागू हैं, वहां पर ले जाकर स्पेशल स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर बच्चे मुम्बई के होते हैं, तो यहां के प्रोजेक्ट के तहत उनको सुविधा दी जाती है।

श्री दत्ता मेघे: सर।

श्री सभापति: एक मिनट। इनका क्वैश्चन था कि जिनको बाजू किया, उनको कहीं न कहीं आपने कोई एंपलायमेंट दिया है या उनकी शिक्षा का प्रबंध किया है?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, ऐसा है कि चाइल्ड लेबर में जिन बच्चों को गिना जाता है, वह पांच और चौदह वर्ष के बीच के बच्चों को गिना जाता है। उनको एंपलायमेंट की सुविधा हम नहीं दिला सकते हैं, लेकिन उनको शिक्षा दिलाने का हर संभव प्रयास सरकार करती है।

श्री दत्ता मेघे: सर, मेरा एक ही क्वैश्चन था कि जो बच्चे आप जहां से पकड़ते हैं, वहां पर उन्हें सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? बिहार के छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको आप बिहार भेजते हैं, तो यह सुविधा मुम्बई में उनके लिए क्यों नहीं हो सकती है? मैंने यह पूछा था।

श्री सभापति: चूंकि वे बच्चे बिहार से थे, इसलिए बिहार में भेज दिया।

श्री दत्ता मेघे: सर, उनका पुनर्वास नहीं हुआ। यह मेरा आरोप है।

श्री सभापति: श्री रुद्रनारायण पाणि।

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद, सभापति महोदय। हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो गए हैं। देश के प्रथम प्रधान मंत्री बाल-बालिकाओं के नाम से परिचित हैं, बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक बाल मजदूरी के बारे में गंभीरता से सोचा नहीं गया है। महोदय, यह एक अत्यंत मानवीय प्रश्न है कि बाल मजदूर, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करें।

श्री सभापति: एक मिनट, आप यह क्वैश्चन कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

आपका क्वैश्चन क्या है?

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, मैं सवाल पर आता हूं।

श्री सभापति: नहीं, पहले आ जाओ। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, यह एक अत्यंत मानवीय प्रश्न है, विवेक का प्रश्न है।

श्री सभापति: एक मिनट सुनिए। आपका यह पहला ही क्वैश्चन आया है, इसमें कम से कम यह इंप्रेशन मत बनाइए। आप क्वैश्चन कर सकते हैं।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति महोदय, यह अत्यंत मानवीय प्रश्न है कि किसी भी फैक्टरी में, किसी भी उद्योग में अगर बाल-मजदूरी चले। उसको हम कितना दूर कर पाएंगे, यह एक अलग बात है, सोचने का विषय है। लेकिन, जो होटल में काम करते हैं, उन बाल-बालिकाओं की आयु खाने-पीने की होती है।

श्री सभापति: यह मैं एलाऊ नहीं करूंगा। आपको क्वैश्चन करना हो, तो कर लें।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, मेरा कहना यह है कि जो होटल हैं, भोजनालय हैं, जो बाल-बालिकाएं काम करते हैं, जिनकी खाने-पीने की आयु है, कभी कभी एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है, जो अत्यंत दुर्भाग्य का, दुख का विषय होता है, तो होटलों में, विशेषकर छोटे-छोटे शहरों के छोटे-छोटे होटलों में, हमारी उड़िया भाषा में ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: आपका कोई क्वैश्चन नहीं है।...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका अगर कोई क्वैश्चन नहीं है, तो उत्तर नहीं आएगा।

श्री रुद्रनारायण पाणि: महोदय, मेरा सीधा सवाल यह है कि खाने-पीने के जो भोजनालय होते हैं, उनमें बाल-मजदूरी का संपूर्ण उन्मूलन करने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? इस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, मैं सम्मानित सदस्य से पूर्ण सहमत हूं, इसलिए कि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य हैं। सरकार का हर संभव प्रयास और श्रम मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता बाल श्रम उन्मूलन पर हैं। हमारे देश में लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से 1 करोड़ 26 लाख ऐसे बच्चे हैं, जिनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो प्रोफेशनल फेमिली के होते हैं। कोई कारपेंटर फैमिली का बच्चा होगा, वह स्कूल भी जाता है और अपने मां-बाप के साथ काम भी करता है, वह प्रोफेशनल काम भी सीखता है। इस प्रकार से 50 प्रतिशत बच्चे अपने घर के प्रोफेशनल काम सीखते हैं और 50 प्रतिशत में से सरकार का प्रयास यह है कि जो हैज़र्डस आकुपेशंस हैं, हैज़र्डस प्रोफेशंस हैं, उन पर खास ध्यान सरकार दे रही है। इस प्रकार 5 लाख बच्चों को अब तक इसमें रिहा किया गया है, उन 5 लाख बच्चों को स्कूलों में रखा गया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 4 लाख स्कूल थे, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इन स्कूलों की संख्या 10 हजार तक बढ़ रही है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इस पर होगी, यह आश्वासन मैं सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूं।

SHRI PRASANTA CHATTERJEE: Sir, there are several reports to show that child labour is continuously on the rise. Even international agencies are reporting the same. My supplementary to the hon. Minister is this. I read in an article very recently that many of the schools of the NCLP have been closed down due to delayed disbursement of financial resources. Would the Minister respond to it?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, according to my knowledge, there is no closure of such schools as there is no dearth of funds. The District Magistrates are the Chairmen to these projects in their respective districts. If anything specific can be brought to my notice by the hon. Member, I will act upon it immediately.

डा॰ कुमकुम राय: सभापति जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बाल श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए, सप्लिमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए 5 रुपए प्रति चाइल्ड रखे हैं और 100 रुपए स्टाइपेंड दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के इस घनघोर वातावरण में यदि बच्चे, जो हैज़र्डस काम नहीं हैं, उन कामों में लगकर

अपना जीवनयापन कर रहे हैं, तो क्या मंत्री महोदय बाल श्रमिक की जो आयु-सीमा निर्धारित की गई है, उस आयु-सीमा को और ज्यादा घटाने पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, यह 5 रुपए, जो एक प्रोग्राम के तहत हमने बताए हैं, ये ऐडिशनल हैं, ये पूरे दिन के खाने के लिए नहीं हैं। लड़के को रिअबिलीटेट करने के बाद अपने मां-बाप के पास भेज दिया जाता है और जब वे स्कूल में आते हैं तो उनको न्यूट्रिशस फूड देने के लिए, एक वक्त का खाना देने के लिए ये रुपए रखे गए हैं। इसको जरूर मैं इग्ज़ैमिन करा लूंगा।

डा॰ कुमकुम राय: सर, 5 रुपए में क्या मिलेगा?

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: अगर बढ़ोत्तरी की कोई जरूरत महसूस होगी तो सरकार जरूर बढ़ोत्तरी करेगी।

डा॰ कुमकुम राय: सर, आयु-सीमा पर यदि पुनर्विचार किया जाए तो बहुत से बच्चे कम से कम अपना पेट तो भर सकेंगे।

श्री सभापति: वह आप इनको अलग से दे दीजिए।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: सर, 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे इसमें गिने जाते हैं। मैंने इसके बारे में अभी कोई स्टडी नहीं की है। इनका सुझाव मैंने नोट कर लिया है, हम इसको इग्ज़ैमिन करेंगे।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, two years ago, a distinguished lady from the Minister's home State got the Magsaysay Award for the outstanding work she has done to prevent child labour. What she has shown is that all the projects that she has run, particularly in the State of Andhra Pradesh, are being run at one-fifth or one-tenth of the cost at which the Government programmes are running, and they are having almost double or treble the efficiency. Now, I would like to know whether the hon. Minister would involve people like Shrimati Shanta Sinha and the large network of NGOs who have demonstrated greater success in eradicating child labour than the Government-run programmes.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I also feel proud to say that from my State, Shrimati Shanta Sinha got the Magsaysay Award and her foundation, that is, the Marapadu Venkatarangaiya Foundation is successfully functioning. We have involved Shrimati Shanta Sinha's total organisation into our programmes, and wherever the NGOs are coming forward, we are also involving them in our programmes.